भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 230
उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2023

ग्रामीण, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जाना

230# **श्री सतीश चंद्र दूबे:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण, पिछड़े, जनजातीय और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सहित राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;
(ग) बिहार के विशेषकर जनजातीय/नक्सल प्रभावित/ग्रामीण इलाकों में अभिनिर्धारित जिलों में राज्य-वार विशेषकर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में कितने नए मोबाइल टावर लगाए जाने का विचार है और लगाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित/व्यय की गई है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) सरकार देश के ग्रामीण और मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और द्वीपसमूहों में दूरसंचार कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अलावा देश के सभी बसे हुए गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतनेट परियोजना के तहत सृजित की गई अवसंरचना का उपयोग सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जा सकता है।

(ख) सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) बिहार राज्य सहित पूरे देश में चरणबद्ध रूप से दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 और दिनांक 31.03.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक देश में लगभग 6,14,721 बेस

ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए गए हैं और 1,21,609 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है जिसमें बिहार के 42,813 बीटीएस और 2,912 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। देश में स्थापित किए गए कुल बीटीएस और सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) विभिन्न यूएसओएफ योजनाओं के तहत ग्रामीण, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण सहित बिहार राज्य के लगभग 252 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा बिहार के 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 59 गांवों को 4जी कनेक्टिविटी में अपग्रेड किया जा रहा है। बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 18,324 मोबाइल दूरसंचार टावर स्थापित किए गए हैं जिसमें पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में स्थापित किए गए 26 टावर शामिल हैं।

(घ) दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य के लिए यूएसओएफ की जारी विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं की योजनाओं के तहत 386 करोड़ रुपये आवंटित/संवितरित/व्यय किए गए हैं।

अनुबंध-I

राज्य सभा में "ग्रामीण, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जाना" के बारे में माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2023 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश भर के ग्रामीण, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा:

- देश में दूरसंचार सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का सैचुरेशन। इस परियोजना की अनुमानित लागत 26,316 करोड़ रूपए है।
- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र चरण-II में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करना। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,211 करोड़ रूपए है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम के तहत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करना। इन स्कीमों की अनुमानित लागत 3,637 करोड़ रूपए है।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना और चार राज्यों (नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के आकांक्षी जिलों के दूरसंचार सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7,152 करोड़ रूपए है।
- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के दूरसंचार सेवा से वंचित 354 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना। इस परियोजना की अनुमानित लागत 337 करोड़ रूपए है।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दूरसंचार सेवा से वंचित 85 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज और एनएच 223 पर निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान करना। इस परियोजना की अनुमानित लागत 130 करोड़ रूपए है।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।
- कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी।
- सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड अवसंरचना से जोड़ने हेतु नेटवर्क सृजित करने के लिए भारतनेट परियोजना।

अनुबंध-II

राज्य सभा में "ग्रामीण, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जाना" के बारे में माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2023 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्थापित किए गए कुल बीटीएस और सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 01.04.2019 से 31.03.2020 तक		वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 तक		वर्ष 01.04.2021 से 31.03.2022 तक		वर्ष 01.04.2022 से 31.12.2022 तक	
		स्थापित किए गए कुल बीटीएस	सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	स्थापित किए गए कुल बीटीएस	सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	स्थापित किए गए कुल बीटीएस	सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	स्थापित किए गए कुल बीटीएस	सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	77	7	32	14	48	36	6	62
2	आंध्र प्रदेश	6017	246	3153	55	-84	19	2864	3490
3	अरुणाचल प्रदेश	999	285	213	315	431	451	286	183
4	असम	5213	1624	4491	3	2760	13	1903	0
5	बिहार	17731	2280	8662	602	9710	21	6710	9
6	चंडीगढ़*	328	1	132	0	71	0	58	0
7	छत्तीसगढ	5364	1068	3622	2809	4025	1370	1618	602
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	247	32	109	1	136	4	36	0
9	गोवा	381	0	306	0	369	0	633	0
10	गुजरात	21219	7312	13278	1569	9085	1349	3770	128
11	हरियाणा	4520	6188	5355	6204	3042	6204	2186	6204
12	हिमाचल प्रदेश	2942	27	2324	93	1344	41	1201	2
13	जम्मू और कश्मीर	2976	788	1657	217	1199	87	1270	20
14	लद्दाख		64		19	167	4	193	2

15	झारखंड	5467	109	4833	866	5088	814	2141	42
16	कर्नाटक	-3622	0	5687	0	3921	4	5479	0
17	केरल	4545	0	1404	0	4286	0	2263	0
18	लक्षद्वीप	18	0	1	0	3	9	0	0
19	मध्य प्रदेश	7648	249	7757	2375	5364	2504	2085	177
20	महाराष्ट्र	22878	15825	15128	3368	20585	3171	12682	1778
21	मणिपुर	1609	640	713	464	435	33	264	51
22	मेघालय	1244	98	402	321	833	103	339	3
23	मिजोरम	878	207	333	185	283	64	179	27
24	नागालैंड	1161	28	296	22	193	98	127	0
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1896	0	20246	0	6796	0	1550	0
26	ओडिशा	3545	3858	8521	1900	4799	886	2677	97
27	पुदुचेरी	234	0	155	0	137	0	132	0
28	पंजाब*	5715	4744	5628	117	3489	0	2901	0
29	राजस्थान	6682	361	976	203	5481	49	4631	0
30	सिक्किम	407	3	221	0	285	12	82	25
31	तमिलनाडु	14140	0	8027	0	7261	0	4428	1110
32	तेलंगाना	6487	0	375	0	1247	5272	5495	1723
33	त्रिपुरा	1367	161	470	6	383	16	188	7
34	उत्तर प्रदेश	36951	937	28221	2410	21870	6221	14483	4011
35	उत्तराखंड	4315	9	3303	2	2476	8	963	122
36	पश्चिम बंगाल	23593	887	12706	378	10310	112	7161	203
कुल		215172	48038	168737	24518	137828	28975	92984	20078

* चंडीगढ़ के लिए मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बीटीएस से संबंधित ब्यौरे को पंजाब राज्य के बीटीएस से संबंधित आंकड़ों में शामिल किया गया है।

*****